(9) इन में (उपरोक्त टिप्पणियों के प्रकाश में, एथी इम्पग्नेंडेनोटिस 1 12 अगस्त, 1999 अनुलग्नक पी-2 को रद्द करना होगा।तदनुसार, इस रिट याचिका को 12 अगस्त, 1999 के अनुलग्नक पी-2 को रद्द करने की अनुमति दी गई है।हम यह भी निर्देश देते हैं कि याचिकाकर्ताओं और एल. ई. ई. टी.-99 के माध्यम से प्रवेश पाने वाले अन्य छात्रों की शुल्क संरचना उस शुल्क संरचना के बराबर होनी चाहिए जो बी. टेक के दूसरे वर्ष के छात्रों पर लागू होती है।(1998-पंजाब तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा जारी एल. ई. ई. टी.-99 के सूचना-सह-प्रवेश विवरणिका के भाग-बी के नियम 4.5 के प्रावधान के अनुसार बैच) कार्यक्रम।यदि ऐसे छात्रों से पहले कोई अतिरिक्त शुल्क लिया गया है, तो उसे बाद के वर्षों के लिए शुल्क में समायोजित किया जाएगा।हालांकि, मामले की परिस्थितियों में, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

आरएनआर

वी. के. बाली और जे. एस. नारंग के समक्ष, जे. जे.

गोपाल कृष्ण चतरथ,-याचिकाकर्ता

बनाम

बार काउंसिल ऑफ इंडिया एंड अदर, प्रत्यर्थी

C.W.P. *2000* का सं. 7738

29सितंबर, 2000

अधिवक्ता अधिनियम *(1961* का *25)*-एस. 7 और *49*-बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स, *1975*-भाग *IV,* धारा *B, RI. 2 (1)* जैसा कि *1999* में संशोधित किया गया-वैधता-कानूनी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नियम में संशोधन और ऐसी शिक्षा के मानकों को निर्धारित करने के लिए-संशोधित नियम में उन लॉ कॉलेजों को बंद करने की मांग की गई जो विशेष रूप से शाम के सत्र चला रहे हैं-बार काउंसिल ऑफ इंडिया यह दिखाने में असमर्थ है कि विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय।*1961* के अधिनियम की धारा *7 (1) (*एच*)* का उल्लंघन करने वाले नियम *2 (1)* में संशोधन की घोषणा करते समय राज्य बार काउंसिलों से परामर्श किया गया था और इस तरह भारतीय बार काउंसिल को कानून के अनुसार नियम जारी करने की स्वतंत्रता के साथ इसे निरस्त कर दिया गया है।

यह माना गया कि धारा 7 (1) (एच) और धारा 49 (1) (डी) का अवलोकन निश्चित रूप से हमें इस निष्कर्ष पर ले जाता है कि कानूनी शिक्षा को बढ़ावा देने और कानूनी शिक्षा के मानकों को निर्धारित करने के लिए भारत में विश्वविद्यालयों और राज्य बार काउंसिलों से परामर्श करने की आवश्यकता थी और उक्त परामर्श प्रभावी परामर्श होना चाहिए क्योंकि विश्वविद्यालय कानूनी शिक्षा प्रदान करने में लगे हुए हैं।भारत में विश्वविद्यालयों से कोई परामर्श नहीं किया गया है।इस प्रकार, नियमों के नियम 2 (1) के तहत घोषित संशोधन टिकाऊ नहीं है और भारत में विश्वविद्यालयों और राज्य बार काउंसिलों के परामर्श से धारा

7 (1) (एच) का उल्लंघन है।

संशोधन निरस्त कर दिया जाता है।तथापि, भारतीय विधिज्ञ परिषद, यदि वह उचित समझे, तो कानून के अनुसार नियम जारी करने के लिए स्वतंत्र होगी और हम याचिकाकर्ता के अधिकार को शिक्षा के अधिकार और भारतीय विधिज्ञ परिषद के अधिकार पर सवाल उठाने के लिए खुला छोड़ते हैं कि वह कानूनी शिक्षा को बढ़ावा देने और ऐसी शिक्षा के मानकों को निर्धारित करने के दायरे में नहीं आने वाले नियम बनाए।"

(पारस 25,26 और27)

गोपाल कृष्ण चतरथ, व्यक्तिगत रूप से याचिकाकर्ता।

प्रतिवादी नं. 1 के लिए अधिवक्ता वरिंदर सिंह राठौर

पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ के लिए अधिवक्ता अनुपम गुप्ता।

निर्णय

जे. एस. नारंग जे.

(1) जी.के. चतरथ, जो एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और जो वर्तमान में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं और जो विभिन्न क्षमताओं में पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ के साथ-साथ अन्य विश्वविद्यालयों में कानूनी शिक्षा से जुड़े हुए दावा करते हैं, और जो पिछले 32 वर्षों से पंजाब विश्वविद्यालय के फेलो रहे हैं और कानून के संकाय से सिंडिकेट के सदस्य के रूप में चुने गए हैं और आगे नई दिल्ली स्थित भारतीय कानून संस्थान की गवर्निंग बॉडी के एक चुने हुए सदस्य हैं, ने जनहित याचिका (सी डब्ल्यू पी संख्या 7738 का 2000) और उम्मीदवारों ने जो कानून की तीन साल की डिग्री के लिए दाखिला चाहते हैं चंडीगढ़ में कानून के विभाग (संध्या कॉलेज) में, और जो प्रवेश परीक्षा को पास कर चुके हैं और प्रवेश क्षेत्र के भीतर हैं (सी डब्ल्यू पी संख्या 10363, 10426 और 10517 का 2000), ने ये याचिकाएं दायर की हैं जो भारतीय बार काउंसिल के नियमों के भाग-IV के खंड B के नियम 2(1) में संशोधन को प्रश्न में बुलाती हैं जो कानूनी शिक्षा के लिए कानून कॉलेजों/विभागों को वर्ष 2000-2001 से केवल दिन की सत्र चलाने की आवश्यकता होती है इसके साथ ही भारतीय वकील अधिनियम, 1961 के साथ-साथ भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 39-ए के तहत अवैध, बिना कानूनी अधिकार के, रंगीन अधिकार प्रयोग और अति-वीरेश के रूप में भारतीय बार काउंसिल द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को निरस्त करने का भी आग्रह किया गया है,— 26 मई, 2000 को जारी पत्र, अनुलग्नक P-2 के रूप में। इस आदेश द्वारा, हम, इस प्रकार, इन सभी चार रिट याचिकाओं को निपटाने का प्रस्ताव करते हैं क्योंकि इनमें सामान्य कानून का प्रश्न शामिल है। तथ्यों को, हालांकि, सी डब्ल्यू पी संख्या 7738 का 2000 से निकाला गया है।

(2) संशोधित नियम 2(1) भाग IV के खंड-बी में भारतीय बार काउंसिल के नियम (जिसे आगे "नियम" के रूप में संदर्भित किया जाएगा) जो चुनौती के तहत है, इस

प्रकार पढ़ा जाता है :

"प्रस्ताव संख्या 68/1999 दिनांक 24 अक्टूबर, 1999

संशोधित नियम इस प्रकार पढ़ा जाएगा :

2(1). कि खंड-बी के तहत कानून शिक्षा पूर्णकालिक कॉलेजों के माध्यम से हो सकती है। सभी कानून कॉलेज जो केवल संध्याकालीन सत्र चला रहे हैं, वे अकादमिक वर्ष 2000-2001 के दौरान "दिन" सत्र में परिवर्तित हो जाएंगे, अन्यथा वे भारतीय बार काउंसिल द्वारा संबद्धता की मान्यता के हकदार नहीं होंगे। बशर्ते कि जहां कॉलेज संध्याकालीन पाठ्यक्रम चला रहा है, वहां उन छात्रों को जिन्हें अकादमिक वर्ष 1999-2000 के दौरान पहले वर्ष के संध्याकालीन सत्रों में प्रवेश दिया गया था, पाठ्यक्रम पूरा करने की अनुमति दी जाएगी।"

(3) उपरोक्त संशोधन के माध्यम से भारतीय बार काउंसिल ने केवल संध्याकालीन सत्र चलाने वाले कानून कॉलेजों को बंद करने की मांग की है और बंदी को अकादमिक वर्ष 2000-2001 से प्रभावी बनाया जा रहा है। यदि किसी भी कॉलेज ने संशोधन का पालन नहीं किया तो इससे भारतीय बार काउंसिल द्वारा संबद्धता की मान्यता नहीं मिलेगी। प्रावधान के अनुसार, जिन छात्रों को अकादमिक वर्ष 1999-2000 के दौरान पहले वर्ष के संध्याकालीन सत्रों में प्रवेश दिया गया था, उन्हें पाठ्यक्रम पूरा करने की अनुमति दी जाएगी।

(4) भारतीय बार काउंसिल ने,—अपने पत्र दिनांक 5 जनवरी, 2000 के माध्यम से, देश के विश्वविद्यालयों और कानून कॉलेजों सहित पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ के कानून विभाग को, नियमों में प्रचारित संशोधन का पालन करने के लिए निर्धारित समय सीमा के भीतर उचित कदम उठाने के लिए निर्देशित किया। भारतीय बार काउंसिल ने आगे यह भी मांग की कि इस प्रभाव की सूचना संबंधित विश्वविद्यालय/कानून कॉलेज द्वारा भेजी जानी चाहिए।

(5) यह मामला पंजाब विश्वविद्यालय-प्रतिवादी संख्या 3 की अकादमिक समिति द्वारा उठाया गया है, जिसे विशिष्ट समिति कहा जा रहा है जो कानून विभाग के अकादमिक मामलों से संबंधित है। विचार-विमर्श के बाद, एक सहमति पर पहुंचा गया है कि भारतीय बार काउंसिल द्वारा दिनांक 5 जनवरी, 2000 को पत्राचार किया गया पत्र, पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ के कानून विभाग पर लागू नहीं होता है, इस आधार पर कि यह मामला केवल उन कानून कॉलेजों से संबंधित है जो केवल शाम के सत्रों को चला रहे हैं जबकि विश्वविद्यालय सुबह और शाम के सत्रों को चला रहा है। सहमति पर पहुंचने के बाद, यह संवाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सचिव को दिनांक 5 अप्रैल, 2000 को भेजे गए पत्र के माध्यम से संवादित किया गया था, जिसमें स्पष्ट रूप से यह कहा गया था कि संशोधित नियम पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ के कानून विभाग पर लागू नहीं होते हैं (पत्र की प्रति पीआई के रूप में संलग्न है)। उस पत्र में उल्लिखित दूसरी दलील यह है कि कानून विभाग छात्रों को सामान्य प्रवेश परीक्षा के आधार पर प्रवेश देता है और सफल छात्रों को दो सत्रों यानी सुबह और शाम के सत्र में शिक्षा प्रदान करता है। इस प्रकार, यह एक विशेष रूप से

शाम के सत्रों में चलने वाला विभाग नहीं है।

(6) कानून विभाग को यह स्पष्ट नहीं था कि उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए कारणों को बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा उचित रूप से स्वीकार किया गया था या नहीं क्योंकि 5 अप्रैल, 2000 को भेजे गए पत्र के प्रत्युत्तर में कोई संवाद/उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था। इसके परिणामस्वरूप, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से कानून विभाग की सहमति के संबंध में प्रतिक्रिया मांगते हुए 11 मई, 2000 को एक अनुस्मारक पत्र भेजा गया था। एक और संवाद दिनांक 22 मई, 2000 को संबोधित किया गया था। यह था, - दिनांक 26 मई, 2000 के पत्र के माध्यम से बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने पंजाब विश्वविद्यालय के कानून विभाग को उत्तर दिया, जिसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने यह इच्छा व्यक्त की कि सभी कानून शिक्षा संस्थानों को शैक्षणिक वर्ष 2000-2001 से शाम के सत्रों को बंद कर देना चाहिए और आगे समझाया गया कि यदि कोई संस्था केवल शाम के सत्र चला रही है, तो उसे शाम के सत्र को "दिन" के सत्रों में बदलने की योग्यता है। कानून विभाग की याचिका को बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा स्वीकार नहीं किया गया, लेकिन उसी समय पोस्ट स्क्रिप्ट में यह जोड़ा गया था कि नियम को देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में रिट याचिकाओं के माध्यम से चुनौती दी गई है। इस प्रकार, शाम के कोर्स में कानून पाठ्यक्रम लेने वाले छात्रों की योग्यता न्यायालयों के निर्णय पर निर्भर होगी। पत्र की प्रति पी2 के रूप में संलग्न की गई है। हालांकि, पत्र के संबंधित अंश को देखना उचित होगा जो इस प्रकार पढ़ा जाता है।

> "बार काउंसिल ऑफ इंडिया चाहती है कि सभी कानून शिक्षण संस्थान शैक्षणिक सत्र 2000-2001 से शाम के सत्रों को बंद कर दें। अगर कोई संस्थान केवल शाम का सत्र चला रहा है, तो वह शाम के सत्र को दिन के सत्र में बदलने के लिए योग्य है और अगर वह शाम और दिन दोनों सत्र चला रहा है, तो उसे शाम के सत्र को बंद करना होगा और केवल दिन के सत्र को जारी रख सकता है। दिन का सत्र का मतलब है 5 घंटे और 30 मिनट की निरंतर पढ़ाई जिसमें सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे के बीच किसी भी समय अधिकतम एक घंटे का ब्रेक हो सकता है।
>
> इन परिस्थितियों में आपके इस तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि यह नियम आपके विभाग पर लागू नहीं होता है।"
>
> xxx xxx xxx xxx
>
> पीएसःहालांकि इस नियम को कुछ उच्च न्यायालयों में रिट याचिकाओं के माध्यम से चुनौती दी गई है और शाम के सत्रों में कानून का पाठ्यक्रम करने वाले छात्रों की पात्रता न्यायालय के निर्णय के अधीन होगी।"

(7) याचिकाकर्ता ने अपने प्रयास में यह दिखाने के लिए तीन गुना प्रस्ताव उठाए हैं कि नियमों में विवादित संशोधन टिक नहीं सकता है। हालांकि, हम याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए बिंदुओं पर विलंब करने से पहले, यह उपयोगी होगा कि हम संक्षेप में मामले के न्यूनतम तथ्यों को दें।

(8) पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़, पंजाब विश्वविद्यालय अधिनियम, 1947 के तहत स्थापित किया गया था और यह कानूनी शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में छात्रों की जरूरतों को पूरा करता है। इसका कानून विभाग देश में, विशेषकर उत्तरी क्षेत्र में, कानूनी शिक्षा के अग्रणी संस्थानों में से एक होने का दावा करता है। भारतीय बार परिषद ने इसके द्वारा प्रदत्त कानूनी डिग्री को वकील के रूप में नामांकन के लिए एक योग्यता के रूप में मान्यता प्रदान की है। याचिकाकर्ता का सकारात्मक मामला है, जैसा कि पैराग्राफ 3 में दावा किया गया है, कि कानून विभाग में दो सत्रों, यानी सुबह और शाम को कक्षाएं होती हैं, जिसके लिए भारतीय बार परिषद की आवश्यकता के अनुसार पूर्णकालिक स्टाफ प्रदान किया गया है। कानून विभाग में दोनों सत्रों के लिए प्रवेश प्रवेश परीक्षा के आधार पर किया जाता है और छात्रों को प्रवेश परीक्षा के परिणाम में निर्धारित अंतरगत योग्यता के आधार पर स्वीकार किया जाता है तथा योग्यता परीक्षा में अंकों के लिए वेटेज भी दिया जाता है। भारतीय बार परिषद ने नियमित कानून कॉलेज या विश्वविद्यालयों के विभागों को परिभाषित किया है और कक्षाओं में अध्ययन के न्यूनतम घंटों और संपर्क, पुस्तकालय आदि सहित सप्ताह में कुल घंटों की अध्ययन को पूर्णकालिक कॉलेज/विभाग के रूप में माना जाने के लिए निर्धारित किया है और पंजाब विश्वविद्यालय सुबह और शाम के सत्रों के दौरान सप्ताह में भारतीय बार परिषद द्वारा निर्धारित घंटों के अनुसार कक्षा कक्ष शिक्षण प्रदान करता है। ये दोनों सुबह और शाम के सत्रों के लिए पूर्णकालिक संस्थान/कॉलेज हैं। 12 सितंबर, 2000 को दिए गए अतिरिक्त हलफनामे में, यह पुन: कहा गया है कि पंजाब विश्वविद्यालय का कानून विभाग प्रवेश परीक्षा के आधार पर सुबह और शाम के सत्रों में प्रवेश करता है और दोनों सत्रों में पूर्णकालिक कॉलेज/विभाग के रूप में शिक्षा प्रदान करता है।

(9) जो लिखित वक्तव्य प्रतिवादी बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से दाखिल किया गया है, उसमें उपरोक्त उल्लेखित तथ्यों का खंडन नहीं है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने केवल इतना कहकर संतोष व्यक्त किया है कि इन आरोपों का कोई उत्तर या टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।

(10) प्रार्थी द्वारा उठाए गए तर्कों पर लौटते हुए, सबसे पहले यह तर्क दिया गया है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया को कानूनी शिक्षा के प्रचार और इस तरह की शिक्षा के मानक तय करते समय देश की विश्वविद्यालयों और राज्य बार काउंसिलों की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त करनी चाहिए थी। इस संबंध में, एडवोकेट्स एक्ट, 1961 के धारा 7(1) (h) का उल्लेख किया गया है। धारा 7 मुख्य रूप से बार काउंसिल ऑफ इंडिया के कार्यों से संबंधित है, संबंधित हिस्सा इस प्रकार पढ़ा जाता है:-

> "7. बार काउंसिल ऑफ इंडिया के कार्य : (१) बार काउंसिल ऑफ इंडिया के कार्य होंगे: : (a) to (g) xxx xxx xxx xxx (h) to promote legal (e) to (i) xxx xxx xx xxx"

(11) तर्क यह है कि कानूनी शिक्षा के मानकों को तय करने से संबंधित नियम बनाने की शक्ति को धारा ७(१) (एच) के साथ पढ़ा जाना चाहिए जो स्पष्ट रूप से बार काउंसिल ऑफ इंडिया के कार्यों को परिभाषित करता है। जब किसी नियम को बनाया जाता

है या मौजूदा नियम में कोई संशोधन किया जाता है जो कानूनी शिक्षा के मानक से संबंधित है, तो यह अनिवार्य है कि भारत में ऐसी शिक्षा दे रहे विश्वविद्यालयों और राज्य बार काउंसिलों से परामर्श किया जाना चाहिए। परामर्श प्रभावी होना चाहिए और सतही नहीं।

(12) पंजाब विश्वविद्यालय या देश के किसी भी विश्वविद्यालय या राज्य बार काउंसिलों के साथ कोई परामर्श न होने के कारण, याचिकाकर्ताओं का आगे कहना है कि नियम में आपत्तिजनक संशोधन को अनिवार्य प्रक्रिया का उल्लंघन होने के कारण निरस्त किया जाना चाहिए।

(13) इन प्रावधानों की एक और तथ्य को आगे रखा गया है और एक वैकल्पिक तर्क प्रस्तुत किया गया है कि वास्तव में भारतीय बार काउंसिल ऐसा नियम बनाने के लिए अधिकृत नहीं है जो कानूनी शिक्षा को बढ़ावा देने के बजाय उसे कम करता है। मौजूदा मामले में, उन कॉलेजों को बंद करने की बात की गई है जो संशोधन के माध्यम से शाम के सत्रों में कानूनी शिक्षा दे रहे हैं। वास्तव में, कोई भी ऐसा नियम नहीं बनाया जा सकता था जो भारतीय बार काउंसिल के कार्यों के संबंध में अनिवार्य प्रावधानों के विपरीत चले। शाम के सत्रों को बंद करने के लिए नियम भारतीय बार काउंसिल के किसी भी सांविधिक कार्यों के निष्पादन के लिए नहीं बनाया गया है। किसी भी कल्पना से, नियम में संशोधन को "कानूनी शिक्षा को बढ़ावा देने और ऐसी शिक्षा के मानकों को तय करने" के लिए पढ़ा नहीं जा सकता। नियम बनाने वाले प्राधिकरणों द्वारा बनाया गया नियम उनके सांविधिक कार्यों से परे है और, इसलिए, आवश्यक रूप से कानून में अल्ट्रा-वायरस और अकार्यकारी होना चाहिए।

(14) इस संबंध में, वी. सुदीर बनाम भारतीय बार काउंसिल और एक अन्य के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर भरोसा किया गया है। हमें डर है कि उद्धृत प्राधिकरण सीधे तौर पर मुद्दे पर नहीं है। उस मामले में शामिल प्रश्न पूरी तरह से अलग था यानी क्या धारा 7 के साथ पढ़कर धारा 49 के तहत शक्ति का उपयोग करके एक वकील के लाइसेंस के अनुदान से पहले पूर्व-पंजीकरण प्रशिक्षण के लिए नियम/प्रावधान बनाए जा सकते हैं। यही संदर्भ में भारतीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अधिनियम की धारा 7(1)(h) और धारा 49 के तहत शक्ति की जांच की गई है। हालांकि, उसी निर्णय से यह मार्गदर्शन लिया जा रहा है कि क्या एक नियम बनाने का अधिकार जिसके द्वारा शाम के सत्रों में जहां कानूनी शिक्षा दी जाती है, उसे समाप्त किया जा सकता है? हमारे अनुसार, उत्तर उच्चतम न्यायालय द्वारा ऊपर उल्लिखित निर्णय में निहित तर्कों में नहीं मिल सकता है। हालांकि, तर्क यह है कि शाम की कक्षाओं को बंद करने से, किसी भी तरह से कानूनी शिक्षा को बढ़ावा नहीं दिया जाता है या कानूनी शिक्षा के मानक निर्धारित नहीं किए जाते हैं, फिर भी सामने आता है।

(15) तीसरे, याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के तहत गारंटीड है। यह इस देश के हर नागरिक का अधिकार है कि वह अपने आप को शिक्षित करे जैसा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 में निहित है। यह तर्क दिया गया है कि एक व्यक्ति जो किसी भी संस्था में रोजगार लेता है, चाहे वह सरकारी हो या निजी, उसे फिर भी अपने आप को शिक्षित करने का अधिकार है और शाम के सत्रों में दी

जा रही कानूनी शिक्षा को संविधान के तहत गारंटीड अधिकार के विरुद्ध चलाए जा रहे प्रावधानों द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता है। यह अलग बात है कि भारतीय संविधान के तहत निहित अधिकारों को उचित प्रतिबंधों के द्वारा समर्थित किया जा सकता है जो कि अधिकारियों द्वारा रंगीन अभ्यास के शक्ति से दूषित नहीं होते हैं। चुनौती के तहत नियम सीधे तौर पर भारतीय संविधान के तहत गारंटीड अधिकार का उल्लंघन करता है जो एक व्यक्ति का हकदार है जो कानूनी शिक्षा का दावा कर सकता है जो कि केवल शाम को चलाए जा रहे लॉ कॉलेजों द्वारा शाम के सत्रों में प्रदान की जा रही थी। यदि ऐसे कॉलेजों को दिन के सत्रों में बदलने के लिए कहा जाता है, तो नियमित रूप से नौकरी करने वाले व्यक्ति विशेष रूप से, कानूनी शिक्षा को प्राप्त नहीं कर पाएंगे।

(16) इसके अलावा यह तर्क दिया गया है कि शिक्षा का अधिकार जो अभी भी एक व्यक्ति को कानूनी शिक्षा के अलावा अपने आप को शिक्षित करने के लिए उपलब्ध है, उन लोगों का अधिकार जो कानूनी शिक्षा में अपने आप को शिक्षित करना चाहते हैं, वह दूसरों के समान नहीं होगा। शाम के सत्र में कानूनी शिक्षा को इनकार करने का कृत्य भी संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा! शिक्षा, चाहे वह कानूनी शिक्षा हो, विज्ञान शिक्षा हो या कला शिक्षा, हर कोई समान व्यवहार का हकदार है।

(17) इसके अलावा, ऊपर उल्लिखित तीन बिंदुओं पर कानूनी दलीलों के साथ, श्री चटरथ की एक और दलील जो तथ्यों पर आधारित है, यह है कि क्या विवादित संशोधन उन विश्वविद्यालयों पर लागू होगा जहां कानूनी शिक्षा सुबह के साथ-साथ शाम के सत्रों में भी दी जा रही है। शब्द "विशेष रूप से" शाम के सत्रों को चलाने पर जोर दिया गया है। पंजाब विश्वविद्यालय का उदाहरण लिया गया है जहां कानून विभाग सुबह के सत्र में भी और शाम के सत्र में भी कानूनी शिक्षा प्रदान करता है। याचिकाकर्ता का कहना है कि नियम केवल उन्हीं कानूनी महाविद्यालयों पर लागू होगा जो विशेष रूप से शाम के सत्र चला रहे हैं और जिन्हें अकादमिक वर्ष 2000-2001 के दौरान "दिन के सत्रों" में बदलने के लिए कहा गया है। यह भी तर्क दिया गया है कि कानून विभाग और विश्वविद्यालय की दलील सही है कि नियम पंजाब विश्वविद्यालय पर लागू नहीं होता। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जब पंजाब विश्वविद्यालय के कानून विभाग द्वारा उठाए गए सवाल का जवाब दिया, तो पहली बार यह समझाने की कोशिश की कि नियम सभी विश्वविद्यालयों पर लागू होता है जहां शाम के सत्र में कानूनी शिक्षा दी जा रही है, जबकि संशोधन इस प्रभाव को स्पष्ट नहीं करता है।

(18) श्री अनुपम गुप्ता, अधिवक्ता, जो पंजाब विश्वविद्यालय के लिए उपस्थित हुए, ने पंजाब विश्वविद्यालय और कानून विभाग की ओर से प्रोफेसर परमजीत सिंह, रजिस्ट्रार, पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा दायर एक हलफनामे को रिकॉर्ड पर रखा जिसमें स्पष्ट रूप से दावा किया गया है कि विवादित नियम को बनाने से पहले विश्वविद्यालय से सलाह नहीं ली गई थी। हलफनामे के संबंधित पैरा कुछ इस प्रकार है -

> "यह कि नियम 2(1) में संशोधन करने से पहले, जिसका पहला संचार बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा पंजाब विश्वविद्यालय को भेजा गया था, उसके लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा विश्वविद्यालय या उसके कानून विभाग के साथ कोई भी प्रकार की परामर्श विधि, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, अपनाई नहीं गई थी, जिसकी

सूचना सबसे पहले बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने पंजाब विश्वविद्यालय को भेजी थी,—सर्कुलर LE (CIR No. 1/2000) दिनांक 5 जनवरी, 2000 (प्रतिलिपि संलग्न) के माध्यम से।"

(19) जहां तक प्रतिवादी पक्ष यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया का संबंध है, हमें यह कहने की मजबूरी है कि इस मामले को निपटाने में इस अदालत की सहायता करते हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने बहुत ही लापरवाह और असावधान रवैया अपनाया है। यह उचित होगा कि विभिन्न आदेशों को नोट किया जाए जो समय-समय पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया को उत्तर दाखिल करने और फिर रिकॉर्ड के प्रदर्शन के लिए अवसर प्रदान करते रहे हैं। यह कहना पर्याप्त होगा कि इस अदालत द्वारा प्रदान किए गए अवसरों के बावजूद, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने संबंधित रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किया है। पहली तर्क के संबंध में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के लिए यह स्पष्ट किया गया है कि यह देखना अत्यंत आवश्यक है कि क्या बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ऐसी शिक्षा प्रदान करने वाली भारत की विश्वविद्यालयों और राज्य बार परिषदों के साथ कोई परामर्श किया था। हमारे 22 सितंबर, 2000 के आदेश में जिसमें समय-समय पर रिकॉर्ड के न-प्रदर्शन से संबंधित तथ्यों का क्रम दर्ज किया गया है, का अंश इस प्रकार है :

xxx xxx xxx xxx

इस रिट याचिका को स्वीकार करते हुए, हमने आदेश में ही उल्लेख किया था कि उत्तर दाखिल किया जाए तीन दिन पहले निर्धारित तिथि से यानी 30 जून, 2000 से और इस तथ्य के बावजूद कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया (संक्षेप में BCI), जो कि प्रतिवादी पक्ष है, को दो बार सेवा प्रदान की गई थी और इसके अनुपस्थिति पर, हमारे अनुरोध पर, याचिकाकर्ता ने BCI के अध्यक्ष श्री सुबराव को सूचित किया और उन्हें एक फैक्स संदेश भी भेजा था कि कोई उपस्थिति नहीं रखी गई थी BCI की ओर से। केवल 11 सितंबर, 2000 को ही मिस्टर वरिंदर सिंह राठौर, अधिवक्ता, BCI की ओर से उपस्थित हुए थे। ऊपर बताई गई सभी बातों का उल्लेख हमने हमारे 11 सितंबर, 2000 के आदेश में किया है।

श्री वरिंदर सिंह राठौर, जो 11 सितंबर, 2000 को BCI का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, ने इस मामले में आगे के निर्देश पाने के लिए समय मांगा। हमने हमारे उक्त आदेश में उल्लेख किया था कि यह एक ऐसा मामला नहीं है जहाँ BCI के अनुरोध को स्वीकार्यता प्राप्त हो सकती है, फिर भी, न्याय के हित में, हमने मामले को 13 सितंबर, 2000 के लिए स्थगित कर दिया। हमने उक्त आदेश में आगे उल्लेख किया है कि मामले की रिकॉर्ड, विशेष रूप से, BCI द्वारा देश में स्थित बार काउंसिलों और यूनिवर्सिटीज़ के साथ परामर्श से संबंधित रिकॉर्ड इस अदालत को नियत तारीख को उपलब्ध कराया जाना चाहिए उपर्युक्त रिकॉर्डों को देखने के उद्देश्य का भी हमारे उक्त आदेश में संकेत किया गया है।

जब यह मामला 14 सितंबर, 2000 को सुनवाई के लिए आया, तो हमारे आदेशों के अनुपालन में जो किया गया था वह यह था कि 5 जनवरी, 2000 की एक पत्र रिकॉर्ड पर रखा गया था जिसमें बी सी आई द्वारा पारित प्रस्ताव का चित्रण किया

गया था जिससे संबंधित नियमों में चुनौती दी गई संशोधन हुआ था। बार काउंसिल्स, यूनिवर्सिटीज़, यू जी सीऔर राज्य सरकारों की तीन दिन की ऑल इंडिया कंसल्टेटिव मीटिंग की कार्यवाही और सिफारिशों की एक रिपोर्ट भी रिकॉर्ड पर रखी गई थी, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा प्रायोजित और आयोजित की गई थी, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया के सहयोग से। हमने 14 सितंबर, 2000 के हमारे आदेश में उल्लेख किया है कि कार्यवाही की रिपोर्ट और सिफारिशों से यह स्पष्ट नहीं था कि देश की बार काउंसिलों के साथ-साथ यूनिवर्सिटीज़ को वकील अधिनियम की धारा 7(l)(h) में निहित प्रावधानों के मद्देनजर परामर्श किया गया था, और आगे रिकॉर्ड उत्पादित नहीं किए गए थे क्योंकि वकील ने कहा था कि यह 1996 के वर्ष से संबंधित है और इसे खोजने में कुछ और दिन लगेंगे। हालांकि, एक बार फिर, न्याय के हित में, हमने मामले को स्थगित किया, विशेष रूप से यह उल्लेख करते हुए कि वकील को रिकॉर्ड तैयार करने और विशेष रूप से उन पत्रों को बनाने के लिए दिया गया था जो तीन दिन की ऑल इंडिया कंसल्टेटिव मीटिंग के अनुसरण में जारी किए गए हो सकते हैं।इस बीच, यूनिवर्सिटी का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील, श्री अनुपम गुप्ता को भी यूनिवर्सिटी के किसी जिम्मेदार अधिकारी द्वारा शपथ पत्र दाखिल करने के लिए कहा गया था, जिसमें यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि नियम संशोधित करने से पहले यूनिवर्सिटी से परामर्श किया गया था या नहीं। पंजाब यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार डॉ परमजीत सिंह का शपथ पत्र दाखिल किया गया है जहाँ से यह स्पष्ट रूप से निकला जा सकता है कि यूनिवर्सिटी को मामले में सलाह नहीं ली गई थी। शपथ पत्र की पैरा 4 इस प्रकार पढ़ता है :

"4. यह कि नियम 2(1) में संशोधन करने से पहले, बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा यूनिवर्सिटी या उसके लॉ डिपार्टमेंट के साथ किसी भी प्रकार का परामर्श, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, नहीं अपनाया गया था, जिसकी सूचना पहली बार बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा पंजाब यूनिवर्सिटी को भेजी गई थी, — परिपत्र LE (CIR No. 1/2000) दिनांक 5 जनवरी, 2000 के द्वारा (प्रतिलिपि संलग्न)।"

यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज भी, श्री राठौर न्यायालय को रिकॉर्ड्स उपलब्ध कराने के लिए स्थगन की मांग कर रहे हैं। हालांकि, वे कहते हैं कि उन्होंने सभी संबंधितों से संपर्क करने और व्यक्तिगत रूप से दिल्ली जाने का जोरदार प्रयास किया है, लेकिन उन्हें रिकॉर्ड्स उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। हालांकि, वे एक पत्र जो 20 सितंबर, 2000 को बीसीआई द्वारा लिखा गया था और श्री वरिंदर सिंह राठौर, अर्थात बीसीआई के लिए काउंसल को संबोधित किया गया था, रिकॉर्ड पर रखते हैं। उस पत्र की सामग्री इस प्रकार है:

"यह पंजाब और हरियाणा के माननीय उच्च न्यायालय में श्री गोपाल कृष्ण चतरथ बनाम विधि विभाग, पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ के मामले में दायर रिट याचिका संख्या 7738/2000 के संबंध में है। निर्णय लिया गया है कि उपरोक्त रिट याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए मुद्दे को विचार में लिया जाएगा कि शाम के कॉलेजों को समाप्त करते समय क्या परामर्श किया गया था, विशेषकर

पंजाब विश्वविद्यालय के साथ, जो कि 22 अक्टूबर, 2000 को निर्धारित कानूनी शिक्षा समिति की अगली बैठक में विचार किया जाएगा।"

उपरोक्त पत्र में जो कहा गया है और निर्देशों पर भी, श्री राठोर हमें सूचित करते हैं कि पूरा मामला 22 अक्टूबर, 2000 को निर्धारित कानूनी शिक्षा समिति की बैठक में पुनर्विचार के लिए है। हमारे सामने जो याचिकाएं और सुझाव दिए गए हैं, उनके लहजे से एक स्पष्ट धारणा बनती है कि न तो देश की राज्य बार काउंसिलों और न ही विश्वविद्यालयों से नियमों में संशोधन करने से पहले परामर्श किया गया था।

xxx xxx xxx xxx

ऊपर कही गई बातों के मद्देनजर और याचिकाकर्ताओं के आग्रह को देखते हुए, जिनका करियर कानूनी शिक्षा का पीछा करने में जोखिम में है, हमें यकीन है कि इस मामले में अंतरिम निर्देश जारी करने की आवश्यकता है। हालांकि, हम बीसीआई को रिकॉर्ड लाने या अगर रिकॉर्ड बीसीआई का समर्थन नहीं करते हैं, तो कोर्ट के सामने यह स्वीकार करने के लिए काफी ईमानदार होने का एक आखिरी मौका देते हैं कि कोई परामर्श नहीं किया गया था।"

(20) हालांकि, रिकॉर्ड की अनुपस्थिति में, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के लिए जानकार वकील ने दायर की गई प्रतिक्रिया और रिकॉर्ड पर लाए गए दस्तावेजों के आधार पर तर्क दिया है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, न्यूनतम तथ्यों पर, जिसका ऊपर संदर्भ दिया गया है और जो याचिका में दावा किया गया है, कोई खंडन नहीं है। हालांकि, यह दलील दी गई है कि एडवोकेट्स एक्ट की धारा 7(1)(h) के तहत, बार काउंसिल ऑफ इंडिया को कानूनी शिक्षा के मानकों को निर्धारित करने और कानून में डिग्रियों की मान्यता का काम सौंपा गया है और बार काउंसिल ऑफ इंडिया को एडवोकेट्स एक्ट की धारा 49 के तहत पूरी तरह से अधिकृत किया गया है कि वह कानूनी शिक्षा के मानकों को निर्धारित कर सकता है और विश्वविद्यालयों को बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित तरीके से कानूनी शिक्षा प्रदान करने का निर्देश दे सकता है क्योंकि कानूनी शिक्षा का अंतिम उद्देश्य छात्रों को कानूनी पेशे में शामिल होने के लिए तैयार करना है, इसलिए, विश्वविद्यालय बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित कानूनी शिक्षा के मानकों का पालन करने के लिए बाध्य हैं। यह आगे दलील दी गई है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया इस मामले में आवश्यकताओं का निर्णय लेने में अधिक योग्य है और इसलिए, उसे प्रोफेशनल कानूनी शिक्षा से संबंधित सभी विषयों पर नियम बनाने की शक्ति है। यह आगे बार काउंसिल ऑफ इंडिया का मामला है कि उसने संशोधित नियम के विर्ट्यू से कानूनी शिक्षा के किसी भी मानक को नहीं निर्धारित किया है और इसलिए, उसे इस मामले में विश्वविद्यालयों और राज्य बार काउंसिलों के साथ कोई परामर्श की आवश्यकता नहीं थी। हालांकि, लिखित वक्तव्य के पैरा 19 में अगली पंक्ति में स्पष्टीकरण के रूप में यह दलील दी गई है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कानूनी शिक्षा प्रदान करने वाले विश्वविद्यालयों और देश के राज्य बार काउंसिलों के साथ कानूनी शिक्षा और कानून में डिग्री की मान्यता के संबंध में परामर्श किया है और अगर नियम को निरस्त किया जाता है, तो यह निश्चित रूप से बार काउंसिल ऑफ इंडिया के कानूनी शिक्षा के मानकों को सुधारने के प्रयासों को प्रभावित करेगा। तथ्यों

पर, संशोधित नियम को सुबह के साथ-साथ शाम के सत्र चलाने वाले संस्थानों/कॉलेजों पर लागू किया जाता है, न कि उन पर, जो केवल शाम का सत्र चलाते हैं।"

(21) इस मामले में आगे बढ़ने से पहले, यह उल्लेख करना आवश्यक है कि भले ही, जब मामला 22 सितंबर, 2000 को सुनवाई के लिए आया, मिस्टर राठोर, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का प्रतिनिधित्व करते हैं, ने विश्वविद्यालयों और राज्य बार काउंसिलों के पूर्व परामर्श की आवश्यकता के संबंध में कानून की स्थिति के बारे में कोई मुद्दा नहीं उठाया, लेकिन केवल तथ्यों पर मुद्दे उठाए, फिर भी बहस के दौरान, उन्होंने जोरदार तरीके से तर्क दिया कि किसी भी प्रकार के ऐसे परामर्श की कोई आवश्यकता नहीं थी। 22 सितंबर, 2000 की तारीख वाले आदेश का संबंधित भाग इस प्रकार है:

> "मिस्टर चतरथ जोरदार तर्क देते हैं कि वकील अधिनियम की धारा 7(1)(h) और 49(1)(d) में उल्लिखित अनिवार्य प्रक्रिया का पालन किए बिना आपत्तिजनक संशोधन नहीं किया जा सकता था। मिस्टर राठोर, जो BCI के लिए पेश होते हैं, केवल तथ्यों पर ही मुद्दे उठा सकते हैं और जहां तक कानून की स्थिति का संबंध है, वह भी विवादित नहीं है।"

(22) कानून की मान्यता किसी पक्ष के खिलाफ बाध्यकारी नहीं हो सकती है, इसलिए श्री राठोर हमारे समक्ष यह तर्क देने के लिए पूर्ण रूप से अधिकारी होंगे कि नियम संशोधित करने से पहले देश में स्थित विश्वविद्यालयों या राज्य बार परिषदों के साथ किसी प्रकार का परामर्श आवश्यक नहीं था।

(23) यह तर्क दिया गया है कि कानून के अनुसार विश्वविद्यालयों और राज्य बार परिषदों के साथ परामर्श करने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि नियम बनाने की शक्ति अधिनियम की धारा 49(1)(डी) के अनुसार विशेष रूप से बार काउंसिल ऑफ इंडिया को दी गई है। यह भी तर्क दिया गया है कि धारा 49(1)(डी) के तहत जो मानक विधिक शिक्षा के लिए निर्धारित किए जाने हैं, वह बार काउंसिल ऑफ इंडिया की नियम बनाने की शक्ति के दायरे में आते हैं और नियम को उचित रूप से प्रवर्तित किया गया है, लॉ कॉलेजों के मशरूम ग्रोथ और उन लोगों को अत्यधिक विधिक शिक्षा प्रदान करने के मद्देनजर जो शायद वकील बनना भी नहीं चाहते हैं। 'शिक्षा के मानक' शब्द निश्चित रूप से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार का अर्थ हो सकता है। उन्होंने आगे तर्क दिया है कि शाम की कक्षाएं उन मानदंडों का पालन नहीं कर रही हैं जो कि एक पूर्णकालिक कॉलेज के लिए आवश्यक हैं। पूर्णकालिक कॉलेज को विशेष रूप से परिभाषित नहीं किया गया है लेकिन इसे नियम 2(2) के अंतर्गत उल्लेखित किया गया है जहां यह अनिवार्य है कि पूर्णकालिक कॉलेज को प्रति सप्ताह कम से कम 30 घंटे कार्य करना चाहिए जिसमें संपर्क और पत्राचार कार्यक्रम, ट्यूटोरियल, घर का काम, पुस्तकालय, क्लिनिकल कार्य आदि शामिल हैं। बशर्ते कक्षा व्याख्यान के लिए वास्तविक समय सप्ताह में 20 घंटे से कम नहीं होना चाहिए। वकील ने अपने तर्क को सिद्ध करने के लिए जबरदस्त प्रयास किया है कि जो लॉ कॉलेज शाम की कक्षाएं चला रहे हैं सहित सभी विश्वविद्यालय इन मानदंडों का पालन नहीं कर रहे हैं, इसलिए यह आवश्यक समझा गया कि शाम की कक्षाएं समाप्त कर दी जाएं बशर्ते वे दिन की कक्षाओं में परिवर्तित हों और पूर्णकालिक कॉलेजों के लिए निर्धारित मानदंडों का पालन करें।

(24) दुर्भाग्य से, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के लिए वकील, किन कारणों से रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं, हमें पता नहीं क्योंकि हमें कोई कारण नहीं बताया गया है। रिकॉर्ड के अभाव में, हम इस तर्क की सराहना नहीं कर पाते हैं और, इसलिए, इसे स्वीकार नहीं कर सकते। हमने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के लिए वकील से स्पष्ट रूप से पूछा था कि यदि वह यह नहीं दिखा सकते कि विश्वविद्यालयों और राज्य बार परिषदों से परामर्श नहीं किया गया था तो याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई पहली दलील अपने आप में आपत्तिजनक संशोधन को निरस्त करने के लिए पर्याप्त होगी। परामर्श दिखाने के उनके प्रयास में, उन्होंने अनुलग्नक R1 का संदर्भ दिया, जो एक संचार था जिसमें 5 जनवरी, 2000 को बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सचिव द्वारा सभी विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार, जो कानूनी शिक्षा प्रदान करते हैं, लॉ के डीन/फैकल्टी और सभी लॉ कॉलेजों के प्रिंसिपलों को भेजा गया था, जिसमें तीन दिवसीय सभी भारतीय परामर्शी बैठक की प्रक्रिया और सिफारिशों का कोई उल्लेख नहीं किया गया था, जिसे वास्तव में बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, बैंगलोर के सहयोग से "कानूनी शिक्षा में सुधार" के संदर्भ में आयोजित और प्रायोजित किया गया था। पत्र के अवलोकन से उक्त परामर्शी बैठक का कोई संदर्भ नहीं दिखता है। वास्तव में, उक्त परामर्शी बैठक से प्राप्त प्रक्रिया की पूरी रिपोर्ट और सिफारिशों से केवल एक बात स्पष्ट होती है कि यह पेशेवर कानूनी शिक्षा में सुधार लाने के संबंध में आयोजित एक सेमिनार थी। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के लिए वकील ने यह निश्चित और स्पष्ट बयान नहीं दिया है कि वास्तव में विश्वविद्यालयों और राज्य की बार परिषदों से कोई परामर्श नहीं हुआ था। किसी भी रिकॉर्ड के अभाव में, जो जानबूझकर अदालत से दूर रखा गया लगता है, एक अप्रतिरोध्य निष्कर्ष जो निकाला जा सकता है वह यह है कि विश्वविद्यालयों और राज्यों की बार परिषदों से नियम संशोधन प्रचारित करते समय परामर्श नहीं किया गया था। 22 सितंबर, 2000 को, श्री राठौर से यहां तक कहा गया था कि वे एक पत्र लाएं जो सभी बार परिषदों के साथ-साथ देश के विश्वविद्यालयों को तीन दिवसीय सभी भारतीय परामर्शी बैठक के लिए भेजा गया हो, लेकिन विशिष्ट निर्देशों के बावजूद वह भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। पत्र को देखने का उद्देश्य यह पता लगाना था कि क्या एजेंडा में शाम की कक्षाओं को बंद करने का कोई उल्लेख था।

(25) ऊपर चर्चा की गई बातों के मद्देनजर, इस चरण पर याचिकाकर्ता द्वारा प्रेस किए गए बाद के दो बिंदुओं को निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं उठती क्योंकि पहला तर्क अपने आप में ही आपत्तिजनक संशोधन को खारिज करने के लिए पर्याप्त होगा। धारा 7(l)(h) और धारा 49(l)(d) की समीक्षा से हमें निश्चित रूप से यह निष्कर्ष निकलता है कि कानूनी शिक्षा को बढ़ावा देने और कानूनी शिक्षा के मानकों को निर्धारित करने के लिए भारत के विश्वविद्यालयों और राज्य बार परिषदों से परामर्श किया जाना आवश्यक था और उस सलाह मशविरे को प्रभावी परामर्श होना चाहिए था क्योंकि विश्वविद्यालय कानूनी शिक्षा का प्रसारण कर रहे हैं। भारत के विश्वविद्यालयों से कोई परामर्श नहीं किया गया है और इस संबंध में हमें पंजाब विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार द्वारा दायर हलफनामे से मजबूती मिलती है, जिसका विशिष्ट पैरा हमने ऊपर नोट किया है कि पंजाब विश्वविद्यालय से नियम 2(1) के तहत किए गए संशोधन के प्रचारण के समय परामर्श नहीं किया गया था।

(26) इस प्रकार, हम यह मानते हैं कि नियम 2(1) के तहत प्रचारित संशोधन, जैसा कि ऊपर नोट किया गया है, टिकाऊ नहीं है और धारा 7(l)(h) का उल्लंघन है क्योंकि यह भारत के विश्वविद्यालयों और राज्य बार परिषदों के साथ परामर्श के बिना प्रचारित किया गया है, इस प्रकार कहा गया संशोधन खारिज किया जाता है।

(27) हम इस चरण पर अन्य दो तर्कों के संबंध में कोई राय व्यक्त करने से स्वयं को बचाते हैं क्योंकि इस संबंध में कोई राय व्यक्त करने का कोई अवसर या कारण नहीं है। हालांकि, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, यदि वह उचित समझे तो कानून के अनुसार नियम प्रचारित करने के लिए स्वतंत्र होगी और हम याचिकाकर्ता के अधिकार को खुला छोड़ देते हैं ताकि वह कहा गया प्रचारण को शिक्षा के अधिकार और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियम बनाने के अधिकार के विपरीत चुनौती दे सके जो "कानूनी शिक्षा को बढ़ावा देने और ऐसी शिक्षा के मानकों को निर्धारित करने" के दायरे के भीतर नहीं आता है।

(28) इस आदेश से अलग होने से पहले, हम उल्लेख करना चाहेंगे कि बिना मानकों की परवाह किए कानूनी शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थानों की बढ़ोतरी से कानूनी पेशे में तबाही आ रही है। ऐसे संस्थानों का विशेष उल्लेख करने की जरूरत नहीं है परंतु यह इंकार नहीं किया जा सकता कि कुछ संस्थान ऐसी कानूनी डिग्रियां प्रदान कर रहे हैं जिनसे कोई भी व्यक्ति बिना किसी कक्षा में उपस्थित हुए कानूनी पेशे में स्वयं को व्यस्त कर सकता है। छात्र, जो अपने घर पर ही पढ़ाई करते हैं, केवल सालाना परीक्षा के समय ऐसे संस्थानों में कुछ दिनों के लिए अस्थाई निवास के लिए यात्रा करते हैं। ऐसे छात्र, सामान्यतः, जब कानूनी पेशे में प्रवेश करते हैं, जिसे एक महान पेशा माना जाता है, उसकी छवि को कम करने में काम करते हैं। ऐसे व्यक्तियों का कानूनी पेशे में प्रवेश तुरंत रोका जाना चाहिए और जितना जल्दी हो सके उतना अच्छा होगा। हालांकि, इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, जो एक स्वागत योग्य कदम होगा और जिसे सभी संबंधितों द्वारा सराहना की जानी चाहिए, कानून के तहत स्थापित प्रक्रिया का पालन करना होगा। ऐसे संस्थानों को निश्चित रूप से पहचाना जाना चाहिए। बहस के दौरान, हमें बताया गया था कि केवल पंजाब विश्वविद्यालय ही मामले में सतर्क था और उसने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को पत्र भेजा था और उसके जवाब प्राप्त होने पर, उसने उन छात्रों को प्रवेश नहीं दिया, जिन्होंने प्रवेश परीक्षा में भाग लिया था लेकिन जहां तक अन्य संस्थानों, जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय के कानून महाविद्यालय और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कानून महाविद्यालय का सवाल है, वे शाम की कक्षाएं जारी रख रहे हैं, जबकि, पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ के कानून महाविद्यालय को सुबह के सत्र में शिफ्ट करने के लिए कहा गया है। इससे स्पष्ट होता है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मानकों का पालन न करने वाले संस्थानों की पहचान करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया है। इस समय यह याद दिलाया जा सकता है कि यह विवादित नहीं है कि चंडीगढ़ में कानून महाविद्यालय, जो सुबह और शाम दोनों सत्रों में छात्रों को प्रवेश देता है, दोनों सत्रों के लिए एक सामान्य प्रवेश परीक्षा के माध्यम से छात्रों को प्रवेश देता है। सुबह और शाम के सत्रों के लिए शिक्षा का मानक समान है और शाम के सत्र में छात्र को वही सभी परीक्षाएं पास करनी पड़ती हैं जो सुबह के सत्र में छात्र को करनी होती हैं, सब कुछ सामान होता है। यह भी अनुत्तरित गया है कि लॉ कॉलेज, चंडीगढ़ देश में कानूनी शिक्षा प्रदान करने में लगे प्रमुख संस्थानों में से एक है और किसी भी मामले में उत्तरी भारत में। संस्था जैसे, पंजाब विश्वविद्यालय का लॉ

कॉलेज, को सुबह के सत्र में बदलने के लिए कहा गया है और, जैसा कि ऊपर बताया गया है ऐसे संस्थान जो वास्तव में डिग्रियां बेच रहे हैं, चाहे सुबह हो या शाम, चाहे कोई छात्र उस संस्थान में कक्षाएं ले या न ले, उनकी पहचान नहीं की गई है और ऐसे संस्थान के संबंध में कोई विशिष्ट आदेश पारित नहीं किये गए हैं। हमारे विचार से, भारतीय बार काउंसिल को ऐसे संस्थानों की पहचान करने और अधिनियम के ढांचे के भीतर ऐसे संस्थानों की पहचान करने और वहां छात्रों की प्रवेश बंद करने के निर्देश जारी करने में अच्छा करेगी।

(29) उपरोक्त चर्चा के लिए, ये याचिकाएं स्वीकार की जाती हैं और भारतीय बार काउंसिल नियमों के खंड B, भाग IV के नियम 2(1) में किए गए आरोपित संशोधन को रद्द किया जाता है। यह स्पष्ट किया जा सकता है कि हमारे सामने आई पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ ने सुबह और शाम के सत्रों की 300 सीटों को भरने के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित की थी। वे उम्मीदवार, जिन्होंने परीक्षा में प्रतियोगिता की थी और शाम के सत्रों के लिए चुना था, उन्हें 2000-2001 के शाम के सत्र में तदनुसार प्रवेश दिया जाएगा।

(30) पक्षकारों को, हालांकि, अपने-अपने खर्च वहन करने के लिए छोड़ दिया गया है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

आयुष
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकार
हिसार, हरियाणा

Gopal Krishan Chatrath *v.* Bar Council of India & others
(J.S. Narang, J.)